(रु०/करोड़)

क्रम सं०	सार्वजनिक/सहकारी क्षेत्र के उपक्रम का नाम	1995-96	1996-97	1997-98
01.	नेशनल फर्टिलाइजर्स लि० (एनएफएल)	54.06	11.20	189.01
02.	फर्टिलाइजर एण्ड केमिकल्स ट्रावनोर लि० (एफएसीटी)	76.76	61.78	53.94
03.	राष्ट्रीय केमिकल्स एण्ड फर्टिलाइजर्स लि० (आरसी एफ)	74.33	76.88	189.37
04.	पाराद्वीप, फास्फेट लि० (पीपीएल)	02.22	(-) 60.63	(-) 105.53
05.	मद्रास फर्टिलाइजर्स लिमिटेड (एमएफएल)	21.07	12.10	(-) 55.35
06.	पाइराइट्स फास्फेटस एण्ड केमिकल्स लिमिटेड (पीपी सीएल)	(-) 00.65	(-) 08.28	(-) 41.80
07.	फर्टिलाइजर कार्पोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड (एफसीआई)	(-) 471.31	(-) 538.02	(-) 724.93
08.	हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर कार्पोरेशन लिमिटेड (एचएफसी)	(-) 474.41	(-)532.64	647.83
09.	प्रोजेक्ट्स एण्ड डेवलपमेंट इंडिया लिमिटेड (पीडीआई एल)	22.52	31.82	06.09
10.	कृषक भारती कोआपरेटिव लिमिटेड (कृभको)	201.95	229.38	299.61
11.	इंडियन फारमर्स फर्टिलाइजर ओर आपरेटिव लिमिटेड (इफको)	132.32	166.42	438.85

उर्वरक विभाग निजी क्षेत्र की उर्वरक कम्पनियों के लाभ/हानि का प्रक्षेपन नहीं करता।

उपर्युक्त में से सार्वजनिक क्षेत्र के एचएफसी, एफसीआई, पीपीसीएल, पीपीएल और एमएफएल नामक पांच उपक्रम हानि उठा रहे हैं। इनकी हानि के मुख्य कारण नीचे दिये गये हैं:—

उपक्रमों का पुरानापन, बिजली की कमी और फालतू जनशक्ति एफसीआई तथा एचएफसी द्वारा उठाई जा रही हानि के मुख्य कारण हैं। जहां तक पीपीसीएल का सम्बन्ध है, पाइराइट्स आधारित सल्फयूरिक एसिड उत्पादन की आन्तरिक लागत हानि और मसूरी में गहरे भूमिगत खनन की बढ़ती हुई लागतें महत्वपूर्ण कारण हैं। जहां तक पीपीएल का सम्बन्ध है, ठेका श्रमिक समस्याएं, फास्फोरिक एसिड संयंत्र के कम क्षमता उपयोग के कारण उत्पादन की उच्च लागत तथा विनिमय दर में उतार-चढ़ाव महत्वपूर्ण कारण हैं । एमएफएल द्वारा उठाई जा रही हानियों के लिये, पुनरुद्धार परियोजना को चालू करने में विलम्ब और बढ़ी हुई फीड स्टाक लागतें महत्वपूर्ण कारणों में से हैं।

विनिवेश आयोग द्वारा की गई सिफारिशों तथा बीआईएफआर द्वारा अनुमोदित किये जाने वाले पुनर्वास पैकेज, जैसा भी मामला हो, के आधार पर सरकार हानि उठा रही उपर्युक्त कम्पनियों के नियंत्रणाधीन एककों की—प्रौद्यो—आर्थिक व्यवहार्यता को ध्यान में रखते हुये समुचित कदम उठाने का विचार रखती है। एफसीआई तथा एचएफसी बीआईएफआर को निर्दिष्ट की गई है तथा विस्तृत पुनर्वास प्रस्तावों पर अन्तर—मंत्रालय विचार—विमर्श किये जा रहे हैं। विनिवेश आयोग ने एनएफएल, एफएसीटी, एमएफएल और पीपीसीएल के सम्बन्ध में अपनी सिफारिशें दे दी हैं। विनिवेश आयोग ने एमएफएल के 50% शेयर एक प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया के माध्यम से अनुकूल भागीदार को बेचने की सिफारिश की है। सरकार ने एमएफएल के सम्बन्ध में विनिवेश आयोग की सिफारिशों को सिद्धान्ततः अनुमोदित कर दिया है। इस आयोग द्वारा एफएसीटी, पीपीसीएल और एमएफएल के बारे में की गई सिफारिशों के सम्बन्ध में सरकार द्वारा कोई निर्णय नहीं लिया गया है। पीपीएल को वर्ष 1994 में पर्याप्त राहतें दी गई थीं जिनमें अन्यों के साथ-साथ इसके पूंजी आधार का पुनर्गठन शामिल है। योजनागत ऋणों के पुनर्भुगतान तथा वर्ष 1997-98 के दौरान देय ब्याज के भुगतान को एक वर्ष के लिये आस्थगित कर दिया गया था। सल्फयूरिक एसिड संयंत्र के क्षमता उपयोग में आ रही बाधाओं पर काबू पाने हेतु एक स्कीम भी तैयार की गई है।

Revival Plan for IDPL

1404. SHRI J. CHITHARANJAN:
SHRI GURUDAS DASGUPTA:

Will the Minister of CHEMICALS AND FERTILIZERS be pleased to refer to answer to Unstarred Question 2596 given in the Rajya Sabha on the 10th July, 1998 and state:

(a) whether Government have since finalised the revised rehabilitation plan for the IDPL;

(b) if so, the details thereof; and

(c) if not, the reasons for the delay?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF CHEMICALS AND FERTILIZERS (DR. A.K. PATEL): (a)

to (c) The package for revival of IDPL approved by BIFR on 10.2.1994 was implemented w.e.f. 1.4.1994. The same had, however, failed in the first year of its operation as IDPL could not achieve the targetted levels of production, sales and profitability in the year 1994-95. IDPL management thereafter proposed the modifications in the revival package. The modified package as proposed by IDPL was referred to BIFR for consideration. The BIFR appointed an Operating Agency for undertaking a techno-economic viability study for long term revival measures for IDPL. The reports received in this regard are being processed from all the relevant aspects after giving due considerations to the views/comments of the other concerned Departments and quarters. The matter is still under consideration.

Cancellation of DAP import Contracts

1405. SHRI RAMDAS AGARWAL: Will the Minister of CHEMICALS AND FERTILIZERS be pleased to state:

(a) whether Government's attention has been drawn to a news-item published in the Hindustan Times dated the 18th November, 1998 captioned "DAP import contracts cancelled by HLCL due to inconsistent policies" especially with regard to fixation of prices for DAP, complexed subsidy component and also its disbursal method followed by Central Government;

(b) whether Fertilizer Industry as well as fertilizers Association of India have blamed Government for cancellation of DAP import contracts worth 1.25 lakh tonnes, leading to shortage of Phosphates in the Kharif season; and

(c) if so, what is Government's reaction thereto and the remedial steps proposed to be taken in this regard?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF CHEMICALS AND FERTILIZERS (DR. A.K.PATEL): (a) to (c) DAP is a decontrolled fertilizer. The demand and supply of DAP is regulated by the market forces depending upon the rates of concession and Maximum Ratail Price (MRP) fixed by the Government under the Concession Scheme. No shortages were experienced during the Kharif season. For Rabi '98-99, the Government decided first In August '98 to fix the rates of concessions alone and leave MRPs in respect of DAP and other decontrolled fertilizers to the market forces. But the policy was rolled back in September '98 in the interest of the farmers as the market determined MRPs of DAP were reported to settle at much higher levels than anticipated . The change of policy resulted in cancellation of nearly 1.30 lakh MTs of.

Losses of IPCL

1406. SHRI RAJNATH SINGH SURYA: Will the Minister of CHEMICALS AND FERTILIZERS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that IPCL is recording losses during the current year;

(b) if so, the reasons therefor; and

(c) what steps are being taken to arrest the decline?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF CHEMICALS AND FERTILIZERS (Shri A.K. PATEL): (a) to (c) Yes, Sir. Indian Petrochemicals Corporation Limited (IPCL) incurred a net loss of Rs. 23.81 crore in the first half of the FISCAL year 1998-99. The loss was mainly on account of depressed prices of Polymers products. The company has already initiated several steps including increase in the volumes of production, strict control on costs and higher capacity utilisation.

उत्तर प्रदेश में उर्वरकों की आवश्यकता

1407. श्री मनोहर कान्त ध्यानी: क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 1997-98 की तुलना में वर्ष 1998-99 के दौरान उत्तर प्रदेश को कितनी मात्रा में उर्वरकों की आवश्यकता है;